

Mpse 001

INDIA AND THE WORLD

LIVE MARATHON CLASS

ONLY EXPECTED QUESTIONS

MUST WATCH THIS VIDEO TO REVISE IMPORTANT TOPICS

Question: Emerging trends in India-China relations.

प्रश्न: भारत-चीन संबंधों में उभरते रुझान।

Answer:

1. Economic Cooperation and Trade

आर्थिक सहयोग और व्यापार

India and China have become key trading partners in recent years. Despite political differences, both countries have deepened their economic ties, with trade between them reaching significant levels. China is one of India's largest trading partners, especially in electronics, machinery, and consumer goods. However, India has been concerned about its trade deficit with China and has pushed for greater access to Chinese markets for Indian products.

भारत और चीन हाल के वर्षों में प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन गए हैं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, दोनों देशों ने अपने आर्थिक संबंधों को गहरा किया है, और उनके बीच व्यापार ने महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच प्राप्त की है। चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, और उपभोक्ता सामानों के मामले में। हालांकि, भारत चीन के साथ अपने व्यापार घाटे को लेकर चिंतित है और भारतीय उत्पादों के लिए चीनी बाजारों में अधिक पहुंच की मांग कर रहा है।

2. Border Tensions and Security Issues

सीमा तनाव और सुरक्षा मुद्दे

One of the most significant challenges in India-China relations has been the unresolved border disputes, especially in regions like Ladakh and Arunachal Pradesh. The 2020 Galwan Valley clash between Indian and Chinese soldiers heightened tensions, and both countries have since increased their military presence along the border. While there have been talks and attempts to ease tensions, the situation

remains fragile, and both sides continue to focus on strengthening their defense capabilities.

भारत-चीन संबंधों में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अनसुलझी सीमा विवाद रही है, खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में। 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष ने तनाव को बढ़ा दिया, और उसके बाद दोनों देशों ने अपनी सीमाओं पर सैन्य उपस्थिति को बढ़ा दिया है। हालांकि, बातचीत और तनाव को कम करने की कोशिशें हुई हैं, स्थिति अभी भी नाजुक है, और दोनों पक्ष अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

3. **China's Belt and Road Initiative (BRI) and India's Response** **चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और भारत की प्रतिक्रिया**

China's ambitious Belt and Road Initiative (BRI), which aims to build infrastructure and enhance connectivity across Asia, has been met with resistance from India. India has expressed concerns about the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), a major part of the BRI that passes through disputed territories in Pakistan-occupied Kashmir. India has avoided participation in the BRI, opting instead to focus on strengthening its own regional partnerships, such as with Japan and the United States.

चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), जिसका उद्देश्य एशिया में बुनियादी ढांचे का निर्माण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, भारत से प्रतिरोध का सामना कर रही है। भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को लेकर चिंता व्यक्त की है, जो BRI का एक प्रमुख हिस्सा है और पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर के विवादित क्षेत्रों से गुजरता है। भारत ने BRI में भाग लेने से बचते हुए, इसके बजाय जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

4. **Strategic Competition and Influence in the Indo-Pacific** **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और प्रभाव**

As China's influence grows in the Indo-Pacific region, India has sought to counterbalance China's ambitions. India has strengthened its partnerships with countries like Japan, Australia, and the United States through the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) to ensure a free and open Indo-Pacific. While China's Belt and Road projects expand, India is focusing on promoting its own vision of regional connectivity and maritime security, emphasizing the importance of international norms and laws.

जैसे-जैसे चीन का प्रभाव इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ता है, भारत ने चीन की महत्वाकांक्षाओं का संतुलन बनाने की कोशिश की है। भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के साथ अपने साझेदारी को चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad) के माध्यम से मजबूत किया है ताकि एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को सुनिश्चित किया जा सके। जहां चीन की बेल्ट और रोड परियोजनाएं बढ़ रही हैं, भारत अपने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा के

अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और कानूनों के महत्व को रेखांकित करता है।

5. **People-to-People Ties and Cultural Exchanges**

जनता से जनता के संबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

Despite political and security challenges, India and China share strong cultural and people-to-people ties. Both countries have a long history of cultural exchange, particularly through Buddhism and other cultural connections. In recent years, both nations have worked on enhancing these ties through academic exchanges, tourism, and cultural events. However, political tensions sometimes impact these exchanges, as seen during periods of border disputes.

राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद, भारत और चीन के बीच मजबूत सांस्कृतिक और जन-जन के संबंध हैं। दोनों देशों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान का लंबा इतिहास है, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और अन्य सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से। हाल के वर्षों में, दोनों देशों ने शैक्षिक आदान-प्रदान, पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इन संबंधों को मजबूत करने पर काम किया है। हालांकि, सीमा विवादों के दौर में इन आदान-प्रदानों पर कभी-कभी असर पड़ता है।

Question: What are the objectives of Indian Foreign Policy?

प्रश्न: भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं?

1. **Promotion of World Peace and Security**

दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना

India's foreign policy emphasizes promoting peace and security worldwide. It engages in global peacekeeping operations and works within international organizations like the United Nations to resolve conflicts. For instance, India has contributed significantly to UN peacekeeping missions, showcasing its commitment to maintaining global stability.

भारत की विदेश नीति का उद्देश्य दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग लेकर संघर्षों को हल करने का काम करता है। उदाहरण के तौर पर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो वैश्विक स्थिरता बनाए रखने के प्रति इसके समर्पण को दर्शाता है।

2. **Economic Development and Cooperation**

आर्थिक विकास और सहयोग

India's foreign policy aims to enhance economic development through international trade, investment, and technological cooperation. By fostering global partnerships, India seeks to grow its economy. Initiatives like "Make in India" and "Atmanirbhar Bharat" reflect India's focus on leveraging international collaborations to boost its own economic growth.

भारत की विदेश नीति का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देकर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना चाहता है। 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी योजनाएं भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर देती हैं।

3. Protection of National Interests

राष्ट्रहित की रक्षा

Protecting national security and sovereignty is a central focus of India's foreign policy. It actively addresses issues like border disputes, regional security, and international terrorism. For example, India has consistently worked towards resolving border issues with Pakistan and China and has strengthened its defense relations with various countries.

राष्ट्रहित की रक्षा भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को मजबूत करने के लिए सीमा विवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद जैसे मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करता है। उदाहरण के लिए, भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवादों को सुलझाने की दिशा में लगातार काम किया है और विभिन्न देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है।

4. Cultural Diplomacy

सांस्कृतिक कूटनीति

India's foreign policy also focuses on promoting its rich cultural heritage globally. Through cultural exchanges, art, and literature, India aims to strengthen its global presence and foster goodwill among other nations. The concept of "Atithi Devo Bhava" (The Guest is God) is also promoted through various cultural initiatives.

भारतीय विदेश नीति अपने समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने पर भी जोर देती है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान, कला, और साहित्य के माध्यम से भारत अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने और अन्य देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। 'अतिथि देवो भव' की अवधारणा भी विभिन्न सांस्कृतिक पहलों के माध्यम से बढ़ावा दी जाती है।

5. Strategic Partnerships and Alliances

रणनीतिक साझेदारी और गठबंधन

India works towards establishing strategic partnerships with countries around the world to ensure security, promote trade, and foster technological cooperation. India

has formed strong alliances with nations such as the United States, Russia, and Japan, enhancing its global influence.

भारत दुनिया भर के देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियां स्थापित करने की दिशा में काम करता है ताकि सुरक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिल सके। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, और जापान जैसे देशों के साथ मजबूत गठबंधन बनाए हैं, जिससे उसकी वैश्विक प्रभाविता को बढ़ावा मिलता है।

Question: Discuss the emerging economic cooperation between India and Central Asia.

प्रश्न: भारत और केंद्रीय एशिया के बीच उभरते हुए आर्थिक सहयोग पर चर्चा करें।

1. Trade and Economic Ties

India has been increasing its trade with Central Asian countries, focusing on sectors like energy, pharmaceuticals, and technology. Trade agreements and partnerships are being strengthened to promote economic growth and regional integration.

व्यापार और आर्थिक संबंध

भारत केंद्रीय एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, जिसमें ऊर्जा, दवाइयां और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। व्यापार समझौतों और साझेदारियों को मजबूत किया जा रहा है ताकि आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

2. Energy Cooperation

Central Asia is rich in energy resources, especially oil and natural gas. India has been looking to secure energy supplies from the region, and several partnerships have been formed for oil and gas exploration, including agreements with countries like Turkmenistan.

ऊर्जा सहयोग

केंद्रीय एशिया ऊर्जा संसाधनों से भरपूर है, खासकर तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में। भारत इस क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत है, और तेल और गैस अन्वेषण के लिए कई साझेदारियां बनाई गई हैं, जिसमें तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के साथ समझौते शामिल हैं।

3. Connectivity and Infrastructure Development

India is focusing on improving connectivity with Central Asia through various infrastructure projects, including the Chabahar Port in Iran, which provides access to Afghanistan and Central Asia. Improved transportation routes and trade corridors are key to enhancing economic ties.

कनेक्टिविटी और अवसंरचना विकास

भारत केंद्रीय एशिया के साथ कनेक्टिविटी सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें ईरान में चाबहार पोर्ट जैसे विभिन्न अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं, जो अफगानिस्तान और केंद्रीय एशिया तक पहुंच प्रदान करती हैं। बेहतर परिवहन मार्ग और व्यापार गलियारों का विकास आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

4. Cultural and Educational Exchanges

India has been promoting cultural diplomacy and educational exchanges with Central Asia to deepen bilateral relations. Initiatives include scholarships for students from Central Asia to study in India and cultural programs to promote mutual understanding.

सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान

भारत केंद्रीय एशिया के साथ सांस्कृतिक कूटनीति और शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दे रहा है ताकि द्विपक्षीय संबंधों को गहरा किया जा सके। पहलों में केंद्रीय एशिया के छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं।

5. Strategic and Regional Cooperation

India is looking to strengthen its presence in Central Asia through regional forums like the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC). India aims to play a more prominent role in regional stability, security, and economic cooperation.

रणनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग

भारत केंद्रीय एशिया में अपनी उपस्थिति को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और केंद्रीय एशिया क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (CAREC) जैसे क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग में एक प्रमुख भूमिका निभाने का लक्ष्य रखता है।

Question: Describe India-Japan bilateral relations since World War II.

प्रश्न: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों का वर्णन करें।

Answer:

1. Post-World War II Period and Early Relations

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि और प्रारंभिक संबंध

After World War II, India's relationship with Japan was initially distant, as Japan had been an adversary during the war. However, following India's independence in 1947, both countries began to rebuild their relations. In 1952, Japan and India signed the Treaty of Peace and Friendship, which marked the beginning of diplomatic relations. Though Japan had been defeated and was under U.S. influence, India's approach was neutral, focusing on promoting peace and cooperation in Asia.

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारत और जापान के संबंध शुरुआत में दूर थे, क्योंकि युद्ध के दौरान जापान भारत का प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, दोनों देशों ने अपने संबंधों को फिर से निर्माण करना शुरू किया। 1952 में, जापान और भारत ने शांति और मित्रता का समझौता किया, जो राजनयिक संबंधों की शुरुआत थी। हालांकि जापान हार चुका

था और अमेरिकी प्रभाव में था, भारत का दृष्टिकोण तटस्थ था, जो एशिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित था।

2. Economic Cooperation and Trade Expansion

आर्थिक सहयोग और व्यापार का विस्तार

In the 1980s and 1990s, India and Japan began expanding their economic ties. Japan became one of India's major trade partners and a significant source of foreign investment. Japanese companies, particularly in the automobile and technology sectors, invested heavily in India. A major milestone was the 2000s agreements on economic cooperation, including trade and investment. Japan also became a key player in India's infrastructure development, especially in areas like railways, highways, and urban infrastructure.

1980 और 1990 के दशक में, भारत और जापान ने अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करना शुरू किया। जापान भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों में से एक बन गया और विदेशी निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। जापानी कंपनियों ने विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत में भारी निवेश किया। एक प्रमुख मील का पत्थर 2000 के दशक में व्यापार और निवेश सहित आर्थिक सहयोग पर समझौते थे। जापान ने भारत की अवसंरचना विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई, खासकर रेलवे, राजमार्गों और शहरी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में।

3. Strategic and Defense Cooperation

रणनीतिक और रक्षा सहयोग

Over time, India and Japan began deepening their strategic cooperation, particularly in the defense and security sectors. Both nations share concerns about China's growing influence in the Indo-Pacific region, which has led to enhanced bilateral defense dialogue. In 2008, Japan and India signed a "Joint Declaration on Security Cooperation," marking a significant step towards deeper defense and security collaboration. Both countries also engage in joint military exercises and collaborate in anti-terrorism efforts.

समय के साथ, भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक सहयोग को और गहरा किया, विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में। दोनों देशों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताएं हैं, जिसके कारण द्विपक्षीय रक्षा संवाद को बढ़ावा मिला। 2008 में, जापान और भारत ने "सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा" पर हस्ताक्षर किए, जो रक्षा और सुरक्षा सहयोग की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भी भाग लेते हैं और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग करते हैं।

4. Cultural and People-to-People Ties

सांस्कृतिक और जन-जन के संबंध

India and Japan have shared cultural ties, especially through Buddhism. Cultural exchange between the two nations has been a key aspect of their relationship. In recent years, both countries have worked to strengthen these people-to-people ties

through educational exchanges, tourism, and collaborations in art, music, and sports. Japan's interest in India's ancient heritage and India's interest in Japan's modern technological advancements have fostered mutual respect and understanding.

भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंध हैं, विशेषकर बौद्ध धर्म के माध्यम से। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान उनके संबंधों का एक प्रमुख पहलू रहा है। हाल के वर्षों में, दोनों देशों ने शैक्षिक आदान-प्रदान, पर्यटन और कला, संगीत और खेल में सहयोग के माध्यम से जन-जन के संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया है। जापान की भारत की प्राचीन धरोहर में रुचि और भारत की जापान की आधुनिक तकनीकी प्रगति में रुचि ने आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा दिया है।

5. Recent Developments and Future Prospects

हाल की विकास और भविष्य की संभावनाएँ

In recent years, the relationship between India and Japan has become even closer. Japan's support for India's entry into international forums like the Nuclear Suppliers Group (NSG) and its active participation in the Quad (Quadrilateral Security Dialogue) along with the U.S. and Australia has further solidified the partnership. Both nations are committed to a free and open Indo-Pacific region, and future cooperation is likely to focus on issues like cybersecurity, climate change, and infrastructure development.

हाल के वर्षों में, भारत और जापान के बीच संबंध और भी मजबूत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रवेश के लिए जापान का समर्थन जैसे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत का प्रवेश और यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) में इसकी सक्रिय भागीदारी ने साझेदारी को और मजबूत किया है। दोनों देश स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं, और भविष्य का सहयोग साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, और अवसंरचना विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित होने की संभावना है।

Question: Explain the ways in which Indian Foreign Policy has evolved.

प्रश्न: भारतीय विदेश नीति कैसे विकसित हुई है, इसके तरीकों की व्याख्या करें।

Answer:

1. Post-Independence and Non-Alignment

स्वतंत्रता के बाद और गुटनिरपेक्षता

After gaining independence in 1947, India adopted a policy of non-alignment, aiming to maintain independence in foreign relations without aligning with any major power blocs. This was a significant shift, as India did not want to be drawn into the Cold War rivalries between the United States and the Soviet Union.

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य विदेशी संबंधों में स्वतंत्रता बनाए रखना था, बिना किसी प्रमुख शक्ति समूह के साथ जुड़ने के। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था, क्योंकि भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता में शामिल होने से बचने की कोशिश की।

2. Shift Towards Strategic Alliances

रणनीतिक साझेदारियों की ओर बदलाव

In the post-Cold War era, India shifted its foreign policy towards forming strategic alliances to safeguard national interests. India began strengthening relations with the United States, Russia, and other countries to enhance economic cooperation and security. This change was reflected in India's active participation in global organizations like the United Nations and the World Trade Organization.

शीत युद्ध के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए रणनीतिक साझेदारियों की ओर मोड़ा। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और अन्य देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया, ताकि आर्थिक सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। यह बदलाव भारत की संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसी वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी से स्पष्ट हुआ।

3. Economic Reforms and Globalization

आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण

In 1991, India underwent significant economic reforms, which also impacted its foreign policy. With liberalization and globalization, India began opening up its economy to foreign investment and trade. This shift led to greater international economic integration, and India strengthened its economic ties with major global players, including the European Union, Japan, and the Middle East.

1991 में भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए, जिनका प्रभाव उसकी विदेश नीति पर भी पड़ा। उदारीकरण और वैश्वीकरण के साथ भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश और व्यापार के लिए खोलना शुरू किया। इस बदलाव ने वैश्विक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया और भारत ने प्रमुख वैश्विक शक्तियों, जैसे यूरोपीय संघ, जापान और मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया।

4. Regional Engagement and Security Concerns

क्षेत्रीय जुड़ाव और सुरक्षा चिंताएँ

India's foreign policy also evolved to address regional concerns, particularly in South Asia. The rise of China as a global power and issues like cross-border terrorism have shaped India's approach to regional security. India has actively engaged with its neighbors and strengthened its defense capabilities while participating in regional organizations like the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) and the Shanghai Cooperation Organization (SCO).

भारत की विदेश नीति ने क्षेत्रीय चिंताओं को संबोधित करने के लिए भी विकास किया है, खासकर दक्षिण एशिया में। वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का उदय और सीमा पार आतंकवाद जैसी समस्याओं ने भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण को आकार दिया है। भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव बढ़ाया और क्षेत्रीय संगठन जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भागीदारी बढ़ाई, साथ ही अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया।

5. **Emphasis on Soft Power and Cultural Diplomacy**

सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति पर जोर

In recent years, India has emphasized the use of "soft power" to enhance its global influence. By promoting its rich cultural heritage, arts, and values, India aims to strengthen its position on the world stage. Initiatives like the "International Day of Yoga" and cultural exchanges have helped India build goodwill with other nations.

हाल के वर्षों में भारत ने अपनी वैश्विक प्रभाविता बढ़ाने के लिए "सॉफ्ट पावर" का उपयोग करने पर जोर दिया है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, कला और मूल्यों को बढ़ावा देकर भारत दुनिया के मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। "अंतरराष्ट्रीय योग दिवस" और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसी पहलों ने भारत को अन्य देशों के साथ सद्भावना बनाने में मदद की है।

Question: What is the role of social movements, NGOs, and think tanks in making Indian Foreign Policy?

प्रश्न: भारतीय विदेश नीति बनाने में सामाजिक आंदोलनों, एनजीओ और थिंक टैंक्स की क्या भूमिका है?

Answer:

1. **Influence on Policy Advocacy and Awareness**

नीति वकालत और जागरूकता पर प्रभाव

Social movements and NGOs play a significant role in advocating for issues such as human rights, environmental sustainability, and social justice on an international scale. They help raise awareness about global issues that influence India's foreign policy, including climate change and human rights abuses. For example, NGOs like Greenpeace India have lobbied for stronger environmental policies, influencing India's stance in international climate change negotiations.

सामाजिक आंदोलनों और एनजीओ का वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार, पर्यावरणीय स्थिरता, और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों के लिए नीति वकालत करने में महत्वपूर्ण योगदान है। ये वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं, जो भारत की विदेश नीति को

प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार उल्लंघन। उदाहरण के तौर पर, ग्रीनपीस इंडिया जैसी एनजीओ ने मजबूत पर्यावरणीय नीतियों के लिए लॉबी की है, जिससे भारत की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में स्थिति प्रभावित हुई है।

2. Role in Humanitarian Diplomacy

मानवीय कूटनीति में भूमिका

NGOs contribute to India's humanitarian diplomacy by providing relief and assistance during crises, which enhances India's global image. For example, India's NGOs have been instrumental in providing disaster relief and medical assistance to countries affected by natural disasters, strengthening India's soft power and diplomatic relations with those nations.

एनजीओ भारत की मानवीय कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर संकट के समय राहत और सहायता प्रदान करने में, जिससे भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, भारत के एनजीओ ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों को आपदा राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उन देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों को मजबूती मिली है।

3. Influence on National Security Concerns

राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर प्रभाव

Think tanks in India, such as the Observer Research Foundation (ORF) and the Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA), provide in-depth research and policy recommendations on issues related to national security, foreign relations, and defense. Their research informs Indian policymakers about emerging global trends and security challenges, influencing decisions in areas like defense alliances and counter-terrorism policies.

भारत के थिंक टैंक, जैसे ऑब्जरवर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) और इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (IDSA), राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर गहन शोध और नीति सिफारिशें प्रदान करते हैं। उनका शोध भारतीय नीति निर्माताओं को उभरते वैश्विक रुझानों और सुरक्षा चुनौतियों के बारे में सूचित करता है, जो रक्षा गठबंधनों और आतंकवाद विरोधी नीतियों जैसे क्षेत्रों में निर्णयों को प्रभावित करता है।

4. Shaping Public Opinion and Advocacy

जनमत और वकालत को आकार देना

Social movements and NGOs often shape public opinion regarding foreign policy issues, which can pressure the government to take action. For instance, movements related to the rights of Indian migrants or the campaigns for stronger action against international human rights violations have led to greater awareness and policy shifts, influencing India's diplomatic approach in such matters.

सामाजिक आंदोलन और एनजीओ अक्सर विदेशी नीति मुद्दों पर जनमत को आकार देते हैं, जो सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय प्रवासियों के अधिकारों से संबंधित आंदोलन या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की वकालत करने वाले अभियानों ने जागरूकता बढ़ाई और नीति में बदलाव की ओर अग्रसर किया है, जिससे भारत की कूटनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है।

Question: What is Humanitarian Intervention? Illustrate with suitable examples.

प्रश्न: मानवीय हस्तक्षेप क्या है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या करें।

Introduction:

मानवीय हस्तक्षेप का मतलब होता है एक बाहरी शक्ति या देश का किसी दूसरे देश में तब जाकर हस्तक्षेप करना, जब वहां पर गंभीर मानवीय संकट, जैसे नरसंहार, युद्ध अपराध, या बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हों। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ितों की रक्षा करना और उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करना है, हालांकि यह अक्सर अंतरराष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों से टकराता है।

Answer:

1. Definition of Humanitarian Intervention

मानवीय हस्तक्षेप की परिभाषा

Humanitarian intervention refers to the use of force or diplomatic efforts by a state or group of states to prevent or stop widespread human suffering in another state. It is usually conducted in situations of gross human rights violations, genocide, or when governments fail to protect their own citizens. The goal is to protect vulnerable populations and prevent atrocities.

मानवीय हस्तक्षेप का मतलब है कि एक राज्य या राज्यों का समूह किसी अन्य राज्य में व्यापक मानवीय संकट को रोकने या समाप्त करने के लिए बल प्रयोग या कूटनीतिक प्रयास करता है। यह आमतौर पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों, नरसंहार, या जब सरकारें अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल हो जाती हैं, तब किया जाता है। इसका उद्देश्य कमजोर जनसंख्याओं की रक्षा करना और अत्याचारों को रोकना होता है।

2. Example: NATO Intervention in Kosovo (1999)

उदाहरण: कोसोवो में NATO का हस्तक्षेप (1999)

One of the most notable examples of humanitarian intervention was NATO's military intervention in Kosovo in 1999. The Kosovo conflict involved widespread atrocities

against ethnic Albanians by the Yugoslav government and its military. NATO, without the approval of the United Nations Security Council, intervened to stop the violence and protect civilians. The intervention is still debated, as it did not have UN authorization but is considered a significant humanitarian intervention to prevent further genocide.

मानवीय हस्तक्षेप का सबसे प्रमुख उदाहरण 1999 में कोसोवो में NATO का सैन्य हस्तक्षेप था। कोसोवो संघर्ष में युगोस्लाव सरकार और उसकी सेना द्वारा जातीय अल्बानियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार किए जा रहे थे। NATO ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना हस्तक्षेप किया ताकि हिंसा रोकी जा सके और नागरिकों की रक्षा की जा सके। यह हस्तक्षेप अभी भी बहस का विषय है क्योंकि इसे संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन इसे आगे नरसंहार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण मानवीय हस्तक्षेप माना जाता है।

3. **Example: United Nations Intervention in Rwanda (1994)**

उदाहरण: रवांडा में संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप (1994)

The Rwandan genocide in 1994 saw the mass slaughter of Tutsis by the Hutu majority government. The international community, particularly the United Nations, was criticized for its failure to intervene effectively during the genocide. After the mass killings, the UN and other international bodies intervened to bring peace and assist in post-genocide reconstruction. This highlights the importance of timely and decisive humanitarian intervention to prevent atrocities.

1994 में रवांडा में हुई नरसंहार में हुतू बहुल सरकार द्वारा तुत्सी समुदाय के लोगों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, को इस नरसंहार के दौरान प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने में विफल रहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। बड़े पैमाने पर हत्याओं के बाद, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने शांति स्थापित करने और नरसंहार के बाद पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए हस्तक्षेप किया। यह अत्याचारों को रोकने के लिए समय पर और निर्णायक मानवीय हस्तक्षेप की महत्वपूर्णता को दर्शाता है।

4. **Example: Intervention in Libya (2011)**

उदाहरण: लीबिया में हस्तक्षेप (2011)

In 2011, NATO, under the authorization of the UN Security Council, intervened in Libya during the civil war between Muammar Gaddafi's government and opposition forces. The intervention aimed to protect civilians from attacks by the Libyan government. The intervention ultimately led to the fall of Gaddafi's regime. However, it also resulted in a power vacuum and ongoing instability, which sparked debate about the effectiveness and consequences of humanitarian intervention.

2011 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के तहत NATO ने लीबिया में संघर्ष के दौरान हस्तक्षेप किया, जहां मुअम्मर गद्दाफी की सरकार और विपक्षी बलों के बीच गृहयुद्ध चल रहा था। हस्तक्षेप का उद्देश्य लीबियाई सरकार द्वारा नागरिकों पर किए गए हमलों से उनकी रक्षा

करना था। इस हस्तक्षेप ने गद्दाफी शासन के पतन की ओर अग्रसर किया। हालांकि, इसके परिणामस्वरूप शक्ति का खाली स्थान और निरंतर अस्थिरता हुई, जिससे मानवीय हस्तक्षेप की प्रभावशीलता और परिणामों पर बहस शुरू हुई।

Question: Explain the Realist and Interdependence approaches to the study of India's foreign policy.

प्रश्न: भारत की विदेश नीति के अध्ययन में यथार्थवादी और परस्पर निर्भरता दृष्टिकोणों की व्याख्या करें।

Introduction:

भारत की विदेश नीति को समझने के लिए कई सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जिनमें यथार्थवादी (Realist) और परस्पर निर्भरता (Interdependence) दृष्टिकोण मुख्य हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण में देशों के अपने राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि परस्पर निर्भरता दृष्टिकोण में देशों के बीच सहयोग और साझेदारी पर जोर दिया जाता है। ये दोनों दृष्टिकोण भारत की विदेश नीति को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करते हैं।

Answer:

1. Realist Approach (यथार्थवादी दृष्टिकोण)

The Realist approach focuses on national security and power. According to this approach, countries act in their own interest to protect their security and maintain power. India's foreign policy, especially after independence, has often followed a Realist approach. For example, India's nuclear tests in 1974 and 1998 were done to ensure national security and show its strength to the world. India also focuses on protecting its borders and maintaining a strong military, especially with neighbors like Pakistan and China.

यथार्थवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति पर जोर दिया जाता है। इसके अनुसार, देश अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं और अपनी सुरक्षा की रक्षा करने के लिए काम करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति में यह दृष्टिकोण देखा गया है। उदाहरण के लिए, भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किए, ताकि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और दुनिया में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके। भारत अपनी सीमाओं की रक्षा और मजबूत सैन्य बनाए रखने पर भी ध्यान देता है, खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ।

2. Security and Military Power (सुरक्षा और सैन्य शक्ति)

A key part of Realism is the belief that a country needs military strength to protect itself. India has focused a lot on its defense policies and military power. For instance,

India's strong military and defense ties with countries like Russia show how India uses power to ensure security. It also focuses on being self-reliant in defense matters, which is a Realist idea of maintaining strength.

यथार्थवाद का एक प्रमुख पहलू यह है कि एक देश को अपनी सुरक्षा की रक्षा करने के लिए सैन्य शक्ति की आवश्यकता होती है। भारत ने अपनी रक्षा नीतियों और सैन्य शक्ति पर काफी ध्यान दिया है। उदाहरण के तौर पर, रूस जैसे देशों के साथ भारत के मजबूत रक्षा संबंध यह दर्शाते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति का उपयोग करता है। इसके साथ ही, भारत रक्षा मामलों में आत्मनिर्भर होने पर भी जोर देता है, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण का हिस्सा है।

3. **Interdependence Approach (परस्पर निर्भरता दृष्टिकोण)**

The Interdependence approach focuses on cooperation and mutual benefits between countries. It suggests that in today's world, countries should work together for economic growth, peace, and solving global issues. Since the 1990s, India has followed this approach more by opening up its economy, increasing trade, and working with international organizations like the United Nations, World Trade Organization (WTO), and G20. India has worked with countries to solve problems like climate change, terrorism, and economic challenges.

परस्पर निर्भरता दृष्टिकोण सहयोग और आपसी लाभ पर जोर देता है। यह कहता है कि आज के समय में देशों को आर्थिक विकास, शांति और वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। 1990 के दशक से, भारत ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है, अपनी अर्थव्यवस्था को खोलकर, व्यापार बढ़ाकर और संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन (WTO), और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम किया है। भारत ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और आर्थिक चुनौतियों जैसे मुद्दों को हल करने के लिए देशों के साथ मिलकर काम किया है।

4. **Global Cooperation (वैश्विक सहयोग)**

Under the Interdependence approach, India focuses on building strong ties with other countries to create a peaceful and stable world. For example, India has worked with Japan and the United States in forums like the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) to promote peace and stability in the Indo-Pacific region. India also participates in climate change agreements and international trade deals to help solve global problems.

परस्पर निर्भरता दृष्टिकोण के तहत, भारत दूसरे देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान देता है ताकि एक शांतिपूर्ण और स्थिर दुनिया बनाई जा सके। उदाहरण के तौर पर, भारत ने जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad) जैसे मंचों में काम किया है ताकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा, भारत जलवायु परिवर्तन समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सौदों में भाग लेता है ताकि वैश्विक समस्याओं का समाधान किया जा सके।

5. Combining Both Approaches (दोनों दृष्टिकोणों का संयोजन)

India's foreign policy combines both the Realist and Interdependence approaches. While it focuses on maintaining national security and military strength (Realism), it also understands the importance of economic cooperation and international partnerships (Interdependence). India uses both approaches to balance its security concerns with its desire for peace and global cooperation.

भारत की विदेश नीति दोनों दृष्टिकोणों का संयोजन है। जबकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य शक्ति बनाए रखने पर ध्यान देता है (यथार्थवाद), यह आर्थिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के महत्व को भी समझता है (परस्पर निर्भरता)। भारत दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग अपने सुरक्षा मुद्दों को वैश्विक शांति और सहयोग की चाह के साथ संतुलित करने के लिए करता है।

Conclusion (निष्कर्ष):

भारत की विदेश नीति में यथार्थवादी और परस्पर निर्भरता दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण सुरक्षा और शक्ति पर केंद्रित है, जबकि परस्पर निर्भरता दृष्टिकोण देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देता है। भारत अपनी विदेश नीति में दोनों दृष्टिकोणों का संतुलन बनाए रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को एक साथ प्राथमिकता देता है।